भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1479
3 मई, 2016 को उत्तरार्थ

विषय: बीटी कपास फसल पर कीट संक्रमण

1479 श्री दुष्यंत चैटालाः
श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कपास उत्पादक राज्यों में बीटी कपास फसल में पिंक बॉलवर्म कीट संक्रमण की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को इस कीट के फैलाव को नियंत्रित करने तथा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए समाधान निकालने के लिए इस प्रकार के कीटों पर अध्ययन करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आईसीए आर की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या देश में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए विगत वर्ष 600 करोड़ की लागत पर कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकला; और
(ङ) क्या सरकार का विचार इस मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने/इसमें सुधार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)</u>

(क) एव (ख): खरीफ, 2015 के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भागों से पिंक वाल वर्म के आक्रमण की रिपोर्ट मिली थी।

(ग): सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के माध्यम से सुझाव दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को बीटी कपास के वाल वार्म प्रतिरोध निगरानी करनी चाहिए इसके परिणामस्वरूप और कीट प्रतिरोधी तंत्र (आईआरएम) रणनीतियां पर तैयार करनी चाहिए। आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर द्वारा कीट प्रतिरोधी तंत्र (आईआरएम) रणनीतियां तैयार की गई है और संपूर्ण देश में 15 वर्षों से आईआरएम परियोजना के अंतर्गत इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(घ) एवं (ड.): भारत सरकार ने देश में भारतीय कपास का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार और सूती कपड़े के लिए कच्ची सामग्री का आधार बढ़ाने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2000-01 के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया था। इसमें चार मिनी मिशन शामिल हैं।

मिशन	**उद्देश्य**
मिनी मिशन-I (एम एम-I)	कपास अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का सृजन
मिनी मिशन-II (एम एम-II)	प्रौद्योगिकी और विकास अंतरण
मिनी मिशन-III (एम एम-III)	मंडी यार्ड का विकास
मिनी मिशन-Iv (एम एम-Iv)	ओटाई और दबाई (जी एंड पी) कारखानों का आधुनिकीकरण और उन्नयन

मिनी मिशन-I को बंद कर दिया गया है, लेकिन आईसीएआर द्वारा अनुसंधान और विकास कार्यकलाप लगातार जारी रखा गया। मिली मिशन-II 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) वाणिज्यिक फसल में शामिल किया गया है। मिनी मिशन-III और मिनी मिशन- IV 31 दिसंबर 2010 से बंद कर दिए गए हैं।

****